DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 30 सितंबर 2022 ----------DATED---------- हिन्दुस्तान

दिल से दिल्ली

आज वीपी मेनन को कनॉट प्लेस में कौन कर रहा याद

विवेक शुक्ला

देश की आजादी के बाद जब साढ़े पांच सौ से ज्यादा रियासतों के भारत में विलय की जटिल प्रक्रिया शुरू हुई, तब पूर्व उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल को कदम-कदम पर सलाह वीपी मेनन दे रहे थे। आज 3 सितंबर को उनकी जयंती पर कनॉट प्लेस के केरल क्लब में एक लेक्चर का आयोजन हो रहा है। उसमें मेनन साहब की पड़पौत्री नारायणी बसु बोलेंगी मेनन की शख्सियत पर। मेनन साहब के प्रयासों से ही कनॉट प्लेस में केरल क्लब 1939 में स्थापित हुआ। मेनन साहब बहुत छोटी उम्र में नौकरी करने के लिए दिल्ली आए। वे जब दिल्ली जंक्शन पर उतरे तो उन्हें पता चला कि गर्मियों के कारण सारे सरकारी दफ्तर शिमला चले गए हैं। वे परेशान हो गए। इसी दौरान उनकी जेब भी कट गई। तब एक सिख सज्जन ने उन्हें 15 रुपये दिए। मेनन साहब ने उनसे उनका पता पूछा। सरदार जी ने कहा कि किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, समझना कि उधार उतर गया। मेनन उन रुपयों के सहारे शिमला चले गए। वहां उनकी एक सरकारी नौकरी लग गई। अपने मेहनत के सहारे मेनन साहब अंग्रेज सरकार में ऊंचे ओहदे तक पहुंच गए। स्वतंत्रता के बाद वे सरदार पटेल के मंत्रालय के सचिव बनाए गए। उनकी सलाह को मानते हुए सरदार पटेल ने रियासतों का भारत में विलय किया।

केरल क्लब में डीडीए वाले सीके नायर ▸▸ *पेज 5*

देखें हमारी वेबसाइट
nbtdilsedilli.com

दिल से दिल्ली

केरल क्लब में बेड़ू पाको बारामासा

केरल क्लब में पिछले दिनों ओणम के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और मलयाली भोज का आयोजन हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम की विशेषता यह रही है कि उस दिन मूल रूप से उत्तराखंड के एक नौजवान **सचिन** ने मलयाली गीत गाकर उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। लोक के क्षितिज से उपजा और अंतरराष्ट्रीय फलक तक अपनी धमक पहुंचाने वाला देवभूमि का सुपर-डूपर लोकगीत 'बेड़ू पाको बारामासा' से भला कौन अपरिचित है। गीत का मुखड़ा किसने लिखा और कब से यह लोकजीवन का हिस्सा बना, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही केरल के रहने वाले कर्नल संजीव नैयर ने जगजीत सिंह की कुछ गजलें गाकर साबित कर दिया कि संगीत की ना तो कोई सीमा है और ना ही भाषा। राजधानी के केरल समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र है केरल क्लब। राजधानी में मलयाली अब आपको रीयल एस्टेट के बिजनेस से लेकर रेस्तरां और दिल्ली की फुटबॉल और अस्पतालों को देखते-चलाते मिलेंगे मलयाली। यहां इनकी आबादी दसेक लाख से कम नहीं होगी।

देखें हमारी वेबसाइट
nbtdilsedilli.com

दिल से दिल्ली

केरल क्लब में डीडीए वाले सीके नायर

कनॉट प्लेस के केरल क्लब की दीवार पर बहुत से मलयाली समाज की नामवर हस्तियों के चित्र लगे हैं। उनमें से एक चित्र को आप बार-बार देखते हैं अगर आप दिल्ली के स्वाधीनता के बाद इतिहास को थोड़ा बहुत भी जानते हैं। यह चित्र है **सी कृष्ण नायर** का। वे 1952 और फिर 1957 के लोकसभा चुनावों में बाहरी दिल्ली सीट से निर्वाचित हुए थे। वे कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दिल्ली में उन्हें गांवों का गांधी कहा जाता था। नायर साहब की दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को स्थापित करने में अहम भूमिका रही थी। उन्होंने सांसद रहते हुए लोकसभा में बार-बार रखी कि दिल्ली में एक इस तरह की सरकारी संस्था बनाई जाए, जो दिल्ली वालों को सस्ते दामों पर घर बनाकर दे। उन्हीं की मांग पर डीडीए का गठन हुआ। हालांकि वह जीवनभर किराए के घर में रहे। वे गांधी जी के साथ दांडी मार्च में भी गए थे। केरल क्लब के सक्रिय सदस्य और लेखक एजे फिलिप कहते हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि मयूर विहार में केरल स्कूल के आगे की सड़क का नाम सी कृष्ण के नाम पर कर दिया जाए। फिलहाल उस सड़क का कोई नाम नहीं है।

केरल क्लब में बेड़ू पाको बारामासा ▸▸ *पेज 8*

देखें हमारी वेबसाइट
nbtdilsedilli.com

संजय झील में डेढ़ मेगावाट का सोलर संयंत्र लगेगा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली विकास प्राधिकरण त्रिलोकपुरी स्थित संजय झील में डेढ़ मेगावाट का सोलर संयंत्र लगाने जा रहा है, जिससे आसपास के लगभग 50 पार्कों में बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। इस सोलर संयंत्र की सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि इसका कुछ हिस्सा झील के ऊपर तैरता हुआ होगा। यह पर्यटकों को लुभाने में भी डीडीए की सहायता करेगा।

डीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि संजय झील प्रार्क करीब 170 एकड़ में फैला है, जिसमें से झील का क्षेत्रफल 52.3 एकड़ है। उन्होंने बताया कि झील के मध्य भाग के एक तिहाई हिस्से में तैरने वाले सौर ऊर्जा पैनल लगाकर संयंत्र लगाने की योजना बनाई जा रही है। झील के बाकी हिस्से में पहले की तरह बोटिंग की सुविधा रहेगी। पार्क के सुंदरीकरण के लिए पौधे लगाए जाएंगे।

हिन्दुस्तान
अब अपना विज्ञापन बुक करें
वैवाहिक / रोजगार
श्रद्धांजलि / स्मरण
शिक्षा / संपत्ति / व्यावसायिक
1800-103-1800

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NEW DELHI
FRIDAY
SEPTEMBER 30, 2022

Hindustan Times
MY DELHI

Elevated corridor in west Delhi to ease traffic mess on Ring Rd

Paras Singh
paras@hindustantimes.com

NEW DELHI: Deputy chief minister Manish Sisodia on Thursday launched construction work a slew of infrastructure projects that include construction of a new three lane flyover, addition of lanes to two existing flyovers, and extension of a third one between west Delhi's Punjabi Bagh and Raja Garden.

The new infrastructure will help decongest the Ring Road in west Delhi, said Sisodia while laying down the foundation stone for the works. The new corridor will also provide seamless connectivity between Dhaula Kuan in south Delhi to Azadpur in north Delhi.

"The new flyover will reduce the traffic load on this (west Delhi) section of the Ring Road. It will not only save the time for commuters but will also lead to reduction in fuel consumption. Once completed, the project is estimated to save around 18 lakh litres of fuel and prevent annual emissions of 1.6 lakh [160,000] tonnes of carbon dioxide," said Sisodia, who holds the PWD portfolio.

The minister added that the works will be completed in the next one-and-a-half years.

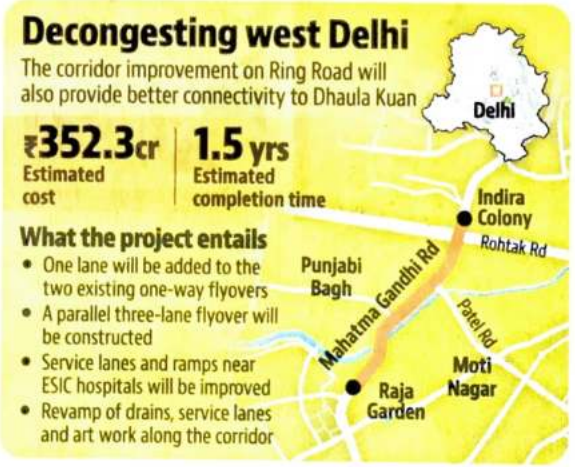

A senior PWD official associated with the project said that Punjabi Bagh has two one-way flyovers located near Raja Garden and Club Road.

"Both of them are two-lane flyovers. Under the corridor improvement project, we will add one lane each to the two existing flyovers and construct a new three-lane flyover that will run parallel to the two structures. In addition to adding one lane each to the two flyovers, they will be extended to make them a contiguous elevated corridor," said the official.

On completion of the work, the flyover at Club Road intersection will provide smooth flow of traffic up to the ESI Hospital on Ring Road.

Explaining the importance of the project, a second official associated with the project said that the traffic load on this section of Ring Road is high as it receives incoming traffic from neighbouring Haryana through National Highway 10 and Rohtak Road. "This is the arterial connection between north Delhi and south Delhi, Gurugram. Hundreds of thousands of commuters use this stretch, resulting in traffic jams specially during peak rush hours," said the second official.

The project also includes the improvement of subway ramps near ESI hospital towards the service road and development of drains, footpaths and strengthening and beautification of existing roads by installing street art-work, Sisodia added

"PWD and our engineers are working on expanding the roads of Delhi and decongesting the city. To achieve the objective, doubling and expanding the flyover at Punjabi Bagh will prove to be a game changer," said Sisodia.

The foundation stone laying ceremony was also attended by MLAs from neighbouring Moti Nagar Shiv Charan Goyal, and Girish Soni of Madipur.

The infrastructure planning arm of DDA – the Unified Traffic and Transportation Infrastructure (planning and engineering) Centre or UTTIPEC had cleared the project in December 2020. The expenditure finance committee of the Delhi government provided the financial approval for the project on May 10, 2022.

Sewa Ram, professor of transport planning at Delhi-based School of Planning and Architecture, said the one-way flyovers work in areas with specific needs. For instance, if there is an intersection where traffic from one side can be shifted to an elevated section, while vehicles from the other side can continue to remain at surface level, such infrastructure may be planned.

"However, if you need to add a lane to make it a two-way flyover, then it means that the designers and planners failed to foresee and the traffic growth at the site. Single carriageway flyovers do not work at intersection of two major roads because at some point, the turning traffic at surface level will begin to have a spillover effect on the other carriageway. There is a life cycle of the intersection that should be kept in mind while making such infrastructure interventions," he added.

He said that similar problems were faced at Rao Tula Ram flyover and Sarai Kale Khan.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022
TIMES CITY
7 ------DATED----------

'World Class' Revamp Of AIIMS Set To Start

18 of 20 Approvals From Different Agencies Secured

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: The redevelopment of All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) into a "world-class medical university" is likely to start soon with the apex committee managing to secure 18 of the 20 statutory approvals from multiple agencies for the implementation of the project.

The committee is yet to get the tree-cutting permission from the forest and environment department despite identifying 26 hectares in Aya Nagar and six hectares in Sultanpur for compensatory afforestation and tree transplantation, said sources. "If all approvals arrive in time, the project will start by the end of this year," said an official.

Lieutenant governor V K Saxena on Thursday chaired the fourth meeting of the committee, constituted to facilitate approvals for implementing the Master Plan of Redevelopment of AIIMS, and reviewed the progress of the project, which has been approved by the Union Cabinet.

AN OFFICIAL SAYS

The only major pending approval is for cutting trees from the forest and environment department, which is awaited for about a month and a half

According to officials, Saxena had emphasised on seamless coordination and expeditious approvals from various agencies, including Delhi Development Authority, Unified Traffic and Transportation Infrastructure (Planning and Engineering) Centre, New Delhi Municipal Council, Delhi Fire Service, Delhi Jal Board, Airport Authority of India, Delhi Urban Arts Commission and Delhi government's departments in the previous meeting on July 26.

Major nods received by the committee include designation of five land parcels belonging to AIIMS for redevelopment in the zonal development plan of Zone F, change of land use, development control norms for a unified campus and transportation plan, allocation of water, fire clearance, and sewage re-routing, and height approval.

"The only major pending approval is that of tree cutting from the forest and environment department, which is awaited for about a month and a half. The LG expressed his displeasure at this inordinate delay that could affect this project of national importance, which promises to augment medical services and education to the people of the country," said an official. "The LG is likely to take up the matter with chief minister Arvind Kejriwal to ensure an early solution," he added.

Sources said that out of the 5,575 trees at the redevelopment site, 2,934 will be retained while 1,910 will be transplanted and 731 to be felled. The project has already received State Environment Impact Assessment Authority's (SEIAA) clearance.

"The project will lead to the removal of 47% of the trees on site. SEIAA tried to get project proponents to reduce removal of trees, but only a few could be saved," said an official.

Officials said the other pending issue was the conversion of five land parcels into one plot allotted to a single lessee by the land and development office, a procedural matter that is likely to be resolved within a few days.

File photo

The committee is yet to get tree-cutting permission from the forest and environment department despite identifying 26 hectares in Aya Nagar and six hectares in Sultanpur for compensatory afforestation

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER: दैनिक जागरण नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2022 DATED----------

लोगों की सुनी तो हाथोंहाथ बिक गए डीडीए के फ्लैट

नई दिल्ली : खरीदारों की जिन आशंकाओं और आपत्तियों की अनदेखी करते हुए डीडीए आठ वर्ष से अपने फ्लैट नहीं बेच पा रहा था, उन आशंकाओं और आपत्तियों पर ध्यान देते ही पुराने फ्लैट हाथोंहाथ बिकने लगे हैं। • पेज 11

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2022 दैनिक जागरण

लोगों की सुनी तो हाथोंहाथ बिक गए फ्लैट

पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 12 सितंबर को डीडीए ने लांच की थी आवासीय योजना

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

खरीदारों की जिन आशंकाओं और आपत्तियों की अनदेखी करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आठ वर्ष से अपने फ्लैट नहीं बेच पा रहा था, उन आशंकाओं और आपत्तियों पर ध्यान देते ही पुराने फ्लैट हाथोंहाथ बिकने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण डीडीए की पखवाड़ा भर पहले लांच आनलाइन आवासीय योजना है, जिसके पहले फेज के सभी फ्लैट 15 दिन में ही बिक गए। डीडीए को लगभग 196.90 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

डीडीए ने 12 सितंबर को आनलाइन आवासीय योजना-2022 लांच की थी। पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर शुरू की गई इस योजना में नरेला उपनगरी में बने 8,530 फ्लैट शामिल किए गए। इनमें 5,850 फ्लैट एलआइजी और 2,880 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। पहले चरण में पोर्टल पर 1,281 फ्लैट ही डाले गए, जिनमें 509 एलआइजी और 772 ईडब्ल्यूएस फ्लैट हैं। योजना में शामिल फ्लैट डीडीए की वर्ष 2014, 2017, 2019 और 2021 की आवासीय योजनाओं में शामिल रहे हैं, जो आवंटियों द्वारा अलग-अलग कारणों से लौटा दिए गए थे।

डीडीए ने फ्लैट नरेला में कई वर्ष पहले बनाए थे, लेकिन कई आवासीय योजनाओं में इन्हें शामिल करने के बावजूद ये बिक नहीं सके। ऐसे में वीके सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) और डीडीए के अध्यक्ष पद संभालने के बाद इस मामले को गंभीरता से लिया। फीडबैक के आधार पर लोगों की आशंकाओं और आपत्तियों को जाना-समझा, जिनमें स्वास्थ्य, परिवहन एवं सुरक्षा से जुड़े मसले प्रमुख थे। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले फ्लैटों को बेचने के नियम में बदलाव किया।

> एलजी की पहल और कोशिशों से खरीदारों की शंकाओं का समाधान हुआ तो फ्लैट बिकने की अड़चनें भी खत्म हो गईं। यह सकारात्मक संकेत है कि 15 दिन में ही पहले फेज में डाले गए सभी 1,281 फ्लैट बिक गए। अब हम सोमवार से इस योजना में दूसरे फेज के 1,200 फ्लैट और डाल रहे हैं। उम्मीद है कि ये भी जल्द ही निकल जाएंगे।
>
> -**वीएस यादव**, आवासीय आयुक्त, डीडीए

योजना के नियमों में ये किए गए बदलाव

- खरीदार की आय के नियम में संशोधन किया गया। पहले खरीदार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये और परिवार की वार्षिक आय दस लाख रुपये से ज्यादा न होने का नियम था। तीन लाख रुपये वार्षिक आय वाले नियम को खत्म कर दिया गया।
- परिवहन व्यवस्था, सुरक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में नरेला से केंद्रीय सचिवालय के बीच डीटीसी की दो बसें चलाने की अनुमति दी।
- नरेला के विभिन्न सेक्टरों में 11 थाने बनाने के लिए पुलिस को जमीन दी गई है। एक चौकी और एक डिस्पेंसरी की तत्काल शुरुआत कर दी गई।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER दैनिक जागरण नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2022 ATED----------

योजना में भाग लेने के बाद भवन की कीमत पर नहीं उठा सकते सवाल

तिनीत त्रिपाठी ● नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, प्राधिकरण की ओर से तय की गई कीमत में अदालत नहीं कर सकती अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

भवन आवंटन से जुड़े एक मामले में एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की आवासीय योजना में एक बार भाग लेने के बाद भवन की कीमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि यह भी पूर्व निर्धारित तथ्य है कि अधिकारियों की ओर से तय फ्लैटों के आवंटन के संबंध में मूल्य निर्धारण के मामलों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकती है।

मनोज कुमार अग्रवाल की याचिका को निरस्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि अदालत में पेश तथ्यों से स्पष्ट है कि यह मामला एक अनिच्छुक खरीदार का है जो रुपये का भुगतान न करने का बहाना ढूंढ रहा है। अपीलकर्ता के अधिवक्ता के इस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि डीडीए ने गलत बयानी की थी। पीठ ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत अपीलकर्ता को मिली जानकारी से पता चलता है कि रेरा की ओर से उठाए गए प्रश्न केवल प्रकृति में स्पष्ट हैं। इसके अलावा डीडीए की स्थायी अधिवक्ता प्रभासहाय कौर ने सूचित किया है कि रेरा ने पहले ही 31 अगस्त 2022 को डीडीए को पंजीकरण प्रदान कर दिया है। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता को 26 सितंबर 2021 को या उससे पहले भुगतान करना था और वह 27 सितंबर 2021 तक दस प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ जमा कर सकता था, लेकिन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसलिए योजना के नियम-10 के अनुसार फ्लैट दूसरों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।

जसोला सहित विभिन्न स्थानों पर डीडीए ने आवासीय योजना-2021 के तहत भवनों के आवंटन के लिए दो जनवरी 2021 को विज्ञापन दिया था। मनोज कुमार अग्रवाल ने इसके लिए आवेदन किया और ड्रा में उनका नाम भी निकला। उन्हें जसोला पाकेट-बी में नौवीं मंजिल पर भवन आवंटित किया गया। साथ ही 30 मार्च 2021 को पत्र जारी किया गया था। इसके तहत उन्हें 1.94 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। उन्होंने पत्र को चुनौती देते हुए 1.94 करोड़ रुपये की मांग पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि लागत जो होनी चाहिए, उससे कहीं अधिक है।

पीड़ित या शिकायतकर्ता को संज्ञेय अपराध केस वापस लेने का अधिकार नहीं : हाई कोर्ट

विसं, प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पीड़ित या शिकायतकर्ता को संज्ञेय अपराध को वापस लेने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार का दायित्व है कि समाज के विरुद्ध अपराध की विवेचना कर अपराधियों को दंडित कराए। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार व अभियुक्त के बीच का मामला होता है। सरकार की कानून व्यवस्था बनाकर अभियुक्त का अभियोजन करने की जिम्मेदारी होती है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन ने हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के बुंदू व 13 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका में आपराधिक केस पक्षकारों में समझौते के आधार खत्म करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया है। 14 लोगों पर दो लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। याचियों पर देसी पिस्तौल से फायर कर घायल करने का आरोप है। पुलिस की चार्जशीट पर कोर्ट ने सज्ञान ले लिया। इसके बाद शिकायतकर्ता इनाम व घायल दानिश ने समझौता कर लिया। इसी आधार पर हाई कोर्ट में धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका दायर कर केस रद करने की माग की। यावी का कहना था आपसी झगड़े में अपराध हुआ है। समाज के खिलाफ अपराध नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी बताते हैं कि संज्ञेय अपराधों को समझौते के आधार पर रद किया जा सकता है, पर कोर्ट ने कहा, फायरिंग कर हत्या की कोशिश समाज और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाला अपराध है। इसे समझौते से खत्म नहीं किया जा सकता।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPE! नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2022 दैनिक जागरण ----DATED----------

एम्स के पुनर्विकास का कार्य जल्द ही शुरू होगा : एलजी

मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए गठित एपेक्स कमेटी की उपराज्यपाल ने ली बैठक, कहा- देरी से प्रभावित होगी परियोजना

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : एम्स के विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्विकास कार्य के जल्द शुरू होने की संभावना है। उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को एम्स को चिकित्सा विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के मास्टर प्लान के कार्यान्वयन के लिए गठित एपेक्स कमेटी की चौथी बैठक ली। इसमें अधिकारियों से लंबित अनुमोदनों की स्थिति पता की और उम्मीद जताई कि सभी मंजूरी मिलने के साथ पुनर्विकास परियोजना पर इस साल के अंत तक सही मायने में काम शुरू हो जाएगा।

बैठक में अधिकारियों ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को बताया कि कई एजेंसियों से 20 वैधानिक अनुमोदनों में से 18 पहले से ही मिल चुके थे और केवल दो लंबित थे। ये 18 मंजूरी एलजी के मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप 26 जुलाई को आयोजित एपेक्स कमेटी की तीसरी बैठक के बाद मिलनी संभव हुईं। एलजी ने डीडीए, एनडीएमसी, डीएफएस, जल बोर्ड, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएआइ) वन विभाग और डीयूएसी जैसे संबंधित विभागों/एजेंसियों से निर्बाध समन्वय और शीघ्र अनुमोदन पर जोर दिया था। एकमात्र प्रमुख लंबित अनुमोदन वन और पर्यावरण विभाग द्वारा पेड़ काटने की अनुमति का था। एलजी ने इस अत्यधिक देरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह देरी इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना को प्रभावित कर सकती है।

एलजी ने कहा कि वह इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बात करेंगे और मामले का जल्द समाधान सुनिश्चित कराएंगे। एलएंडडीओ से जुड़ा लैंड पार्सल का मामला भी लंबित है। यह एक प्रक्रियात्मक मुद्दा है, जो कुछ दिन में पूरा हो जाएगा। बैठक में मुख्य सचिव, डीडीए वीसी, एम्स निदेशक, एनडीएमसी अध्यक्ष, सचिव वन और पर्यावरण, सीईओ डीजेबी, विशेष पुलिस आयुक्त (यातायात) और संबंधित विभागों/एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPA अमर उजाला नई दिल्ली | शुक्रवार, 30 सितंबर 2022

एम्स को विश्वस्तरीय बनाने की कवायद तेज

नई दिल्ली। एम्स को विश्वस्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए गठित शीर्ष कमेटी की बैठक की उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद एम्स के पुनर्विकास मास्टर प्लान को अमलीजामा पहनाने के लिए कमेटी गठित की गई थी। इस परियोजना के लिए 20 में से 18 कार्यों की पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। शेष दो एजेंसियों की स्वीकृति मिलने के बाद पुनर्विकास परियोजना पर जल्द कार्य शुरू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

पुनर्विकास मास्टर प्लान पर साल के अंत तक कार्य शुरू होने की उम्मीद

26 जुलाई को शीर्ष कमेटी की तीसरी बैठक में उपराज्यपाल ने एजेंसियों से निर्बाध समन्वय और शीघ्र अनुमोदन पर जोर दिया था। इनमें संबंधित विभागों, डीडीए, यूटिपेक, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वन विभाग को संबंधित विभाग और एजेंसियां शामिल थीं। इस पुनर्विकास परियोजना के तहत जोन (एफ) के क्षेत्रीय विकास के लिए एम्स से संबंधित पांच भूमि टुकड़ियां (पार्सल), भूमि उपयोग में परिवर्तन, एकीकृत परिसर के विकास के मानदंड और परिवहन योजना को मंजूरी दे दी गई है।

एनडीएमसी, डीजेबी, डीएफएस, डीयूएसी और एएआई की ओर से पुनर्विकास, जल आवंटन, अग्निशमन, सीवेज में बदलाव और ऊंचाई के लिए मास्टर प्लान को मंजूरी के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया गया है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
FRIDAY, 30 SEPTEMBER, 2022 | NEW DELHI

NAME OF NEWSPAPERS ---- TED----

AFFECTED PEOPLE WILL HAVE TO WAIT FOR FEW MORE DAYS

Yamuna water level receding but still above danger mark

OUR CORRESPONDENT

NEW DELHI: The water level in Yamuna in Delhi has receded slightly but it is still above the danger mark of 205.33 metres and the affected people will have to wait for a few more days before they can return to their houses in low-lying areas along the river, officials said on Thursday.

According to the Central Water Commission's data, the water level in the Yamuna dipped from 206.59 metres at 7 am on Wednesday, the highest since August 2019, to 205.37 metres at 9 am on Thursday.It is likely to drop below the danger mark of 205.33 metres during the day.

The city administration had issued a flood alert, suspended rail traffic movement on the Old Yamuna Bridge and evacuated around 6,500 people from low-lying areas close to the Yamuna on Tuesday as the river breached the evacuation mark of 206 metres following a late spell of heavy rain in the upper catchment areas, especially Uttarakhand and Himachal Pradesh, last week.

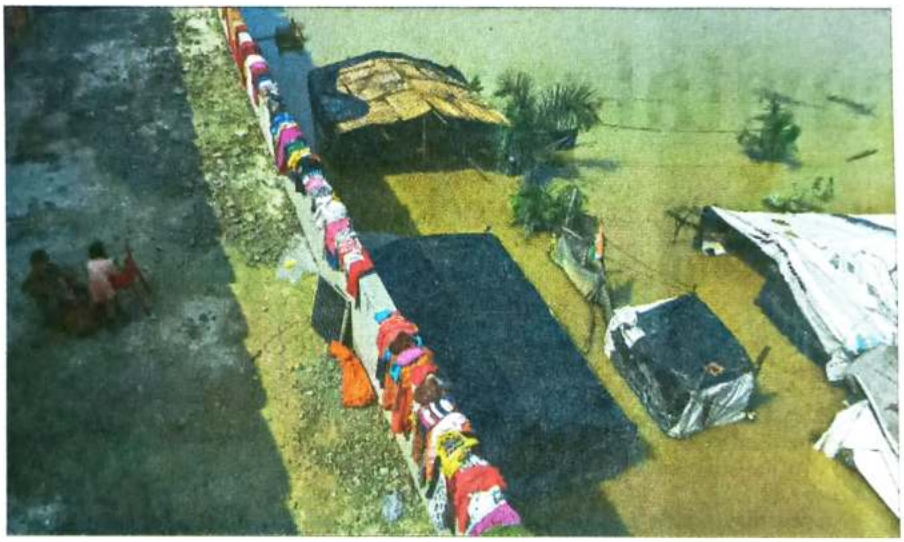

Submerged shanties in a low-lying area near the Yamuna river, in New Delhi, on Thursday PTI

Since there has been no significant rainfall in the upper catchment areas over the last to three days, the water flow rate from Haryana's Hathnikund Barrage has also come down from 96,000 cusecs at 7 am on Tuesday to 25,400 cusecs at 9 am on Wednesday and further to 17,800 cusecs at 9 am on Thursday. One cusec is equivalent to 28.32 litres per second.

Normally, the flow rate at the Hathnikund barrage is 352 cusecs, but the discharge increases after heavy rainfall in the catchment areas.

The water discharged from the barrage normally takes two to three days to reach the national Capital.

Officials said civil defence workers deployed in the affected low-lying areas are asking people not to move back to their houses till the water recedes to the normal level.

The low-lying areas near the river in Delhi are considered vulnerable to flooding and are home to around 37,000 people.

Most of the people shifted to safer places themselves. The Delhi administration had to evacuate around 6,500 people and move them to community centres, schools and temporary tents, an official said.

"We expect the water to recede to normal levels in two to three days. Thereafter, these people can go back to their places," he said.

Though the land along the Yamuna belongs to the Delhi Development Authority, Revenue Department and private individuals, encroachments have come up on a large part of the river floodplains over the years. Normally, flooding in the Yamuna is reported in July or August which receive maximum rainfall during the monsoon season.

Also, this was the second time within two months that a swollen Yamuna inundated low-lying areas in Delhi, forcing people to shift to safer places.

The Yamuna had breached the danger mark of 205.33 metres on August 12, following which around 7,000 people were evacuated from the low-lying areas near the riverbanks.